(ख) किसी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के लिए क्या मापदण्ड हैं और क्या राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाते समय वहां के क्षेत्रफल राष्ट्रीय सीमा, खनिज सम्पदा अथवा सड़कों के अभाव को भी ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई न्यूनतम कि०मी० होने के क्या कारण हैं इस अन्तर को कब तक दूर कर दिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 2931 कि०मी० है। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा सकल देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है न कि किसी प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय आधार पर।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए निम्नलिखित मापदण्ड हैं:—

(1) सड़कें जो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं,

(2) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें,

(3) राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें,

(4) महाफत्तनों एवं महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें,

(5) अत्यधिक महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें,

(6) पर्याप्त लम्बाई तक उच्च यातायात सघनता वाली सड़कें, और

(7) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में पर्याप्त कमी हो तथा जिनसे पर्याप्त आर्थिक बचत हो।

इस प्रयोजन के लिए क्षेत्र, खनिज सम्पदा तथा सड़कों के अभाव जैसे अन्य तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है।

(ग) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कि०मी० लम्बाई मध्य प्रदेश को छोड़कर अधिकतम है।

Buses under DTC

447. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that different types of buses are plying in Delhi under the Delhi Transport Corporation fleet; and

(b) if so, the details thereof giving their respective colour scheme and fare structure?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) yes, Sir.

(b) The details are as under:—

Colour Scheme

(i)	Ordinary buses	— Green and Yellow colours.
(ii)	Green Line Buses	— Green Strip in the mid of the bus body.
(iii)	Private Buses under DTC	— Turquoise Blue colour upto window level and aluminium paint.

Fare Structure

(i)	Ordinary buses	Re. 1.00 (upto 6 kms.) Rs. 2.00 (6—16 kms.) Rs. 3.00 (16 kms. and above)
(ii)	Night/Delux, point to point Limited/Rly. Spl. Services	Rs. 3.00
(iii)	Green Line Buses	: Rs. 4.00 per passenger per trip
(iv)	Tourist Buses	: Rs. 18/- (Ist Trip) Rs. 15/- (IInd Trip) Rs. 30/- (Combined)
(v)	Palam Coach	: Rs. 20/-

करनाल और मूरथल के बीच जी० टी० रोड का चौड़ा किया जाना/चार लेनों वाला बनाया जाना

448. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर**: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मूरथल और करनाल के बीच जी०टी० रोड के दोहरीकरण/चौड़ा किए जाने (चार लेन वाला बनाये जाने) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मूरथल और करनाल के बीच जी०टी० करनाल रोड़ दोहरीकरण/चौड़ा करने (चार लेन वाला बनाने) का प्रस्ताव कब से सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) इस कार्य को आरम्भ करने में मुख्य बाधाएं कौन-कौन सी हैं और उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यह कार्य कब तक आरम्भ/पूरा होने की सम्भावना है और इस पर होने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) जी, हां।

एनएच-1 के 50.00 से 130.00 कि०मी० तक 80 कि०मी० लम्बे मुरथल करनाल खण्ड को चार लेन का बनाने के लिए मार्च 1986 में मंजूरी दी गई थी।

(ग) यद्यपि कार्य 1987 में शुरू हो गया था लेकिन ठेके संबंधी विभिन्न समस्याओं के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही। एक खण्ड में मूल ठेकेदार को हटाना पड़ा था और नए टेंडर आमंत्रित करने के बाद पुनः ठेका दिया गया था। दूसरे मामले में मूल संयुक्त उद्यम फर्म जो टूट गई थी, के एक संघटक के साथ लम्बी बातचीत के बाद एक पूरक ठेके पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) संशोधित शिड्यूल के अनुसार काम पहले ही शुरू हो गया है और इसके दिसम्बर, 1995 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। संपूर्ण कार्य पर लगभग 53.5 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

449. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये थे तथा कितने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, नहीं। योजना आकार, निधियों की उपलब्धता, सकल प्राथमिकताओं इत्यादि के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास कार्य विभिन्न योजना अवधियों में शुरू किए जा रहे हैं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की विकास परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति हेतु 203.40 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी जबकि वास्तव में 246.47 करोड़ रुपए की संस्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी अवधि के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उपलब्ध सकल निधियों में से गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए 124.75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और इसके विपरीत 127.28 करोड़ का व्यय किया गया।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए अभी तक कोई विशेष उपाय नहीं किए गए हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि

450. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क निधि में संशोधित प्राक्कलनों के अनुरूप वृद्धि नहीं की गई है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि में कब तक वृद्धि की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) जी, हां। बजटगत प्रतिबंधों के कारण, दिनांक 13.5.1988 को संसद द्वारा पारित संशोधित संकल्प के अनुसरण में केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) इस समय यह कहना कठिन है कि इसमें कब तक वृद्धि होगी।

दिल्ली में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बसों का चलाया जाना

451. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बसें चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितनी बसें चलाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली में वाहनों की संख्या में हुई अचानक वृद्धि के कारण सड़क सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारी कदम उठाये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) दिल्ली में किसी रूट अथवा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। प्राइवेट सेक्टर दिल्ली में बसों का प्रचालन करता रहा है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा।

(ख) दिल्ली में निजी प्रचालकों के लिए स्टेज कैरिज परमिटों की स्कीम के अंतर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली ने निजी प्रचालकों को 3000 स्टेज कैरिज परमिट देने का निर्णय लिया है। 19.11.1992 को